

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 8 फरवरी 2023

जर्जर नाला बन रहा हादसों की वजह, बदबू से लोगों का जीना हुआ मुहाल

■ एनबीटी न्यूज, महारौली

सराय वॉर्ड में सालों से टूटी सीवर के कारण जहाज महल और झरना इलाके के लोग काफी परेशान हैं। लोगों को हमेशा हादसों का डर बना रहता है। बीते मॉनसून में हुए एक हादसे में बाइक सवार दंपती अपने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ नाले में गिर गए थे। इस कारण बाइक चला रहे शख्स का पैर में फैंक्चर हो गया था। नाले की गहराई और चौड़ाई के चलते कई बाइक और स्कूटर सवारों के यहां एक्सीडेंट हो चुके हैं। नाले की कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। डीडीए के खुले मैदान में इसका गंदा पानी जमा हो रहा है। लोगों का कहना है कि इससे बीमारी फैल रही है।

लोगों का कहना है कि इस समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं जूझ रही हैं। बाहर जाने के बाद घर आने पर जूते-चप्पलों के साथ गंदगी घर में आती है। घर की सफाई

महारौली सुरक्षा कवच वॉट्सऐप ग्रुप की सदस्य ने बताया, गंदगी की वजह से लोग हो रहे हैं बीमार



पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। नाले की बदबू से सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों की शिकायतें विभाग के पास लगातार पहुंच रही हैं। लोगों ने बताया कि सितंबर में लोगों के कड़े विरोध के बाद अधिकारी क्षेत्र में आए थे। लोगों को आश्वासन दिया। मगर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। महारौली सुरक्षा कवच ग्रुप की सदस्य ज्योति डंगवाल ने बताया कि कई साल से लोग नाले की बदबू झेल रहे हैं। शिकायतों के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी इलाके का दौरा करते हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते।



इस सड़क पर अक्सर होते रहते हैं हादसे, लोग हैं परेशान

Hindustan Times

Cops to use smart tech to curb jams ahead of G20 meet

Sanjeev K Jha

sanjeev.jha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Traffic Police has decided to launch a parking alert mechanism and rectify road markings and signages at 290 junctions ahead of the G20 Summit, scheduled to take place on September 9 and 10 in the national Capital.

SS Yadav, the special commissioner of police (traffic), said the main objective of the traffic police will be to reduce traffic bottlenecks with the help of smart and AI tools.

"The thorough traffic surveillance will keep an eagle's eye on even the minor traffic violations. All the damaged and out-of-order traffic lights and signals will soon be repaired. Besides, the traffic police had been mapping all possible routes likely to be used by the dignitaries during the G20 summit," he said.

Apart from the main G20 summit - which will host state heads of 29 countries and chiefs of 15 international organisations, Delhi will also witness seven additional events, starting from the foreign ministers' meet on March 1 and 2.

Yadav further said that besides mapping the VVIP movement, the traffic police have also mapped the vulnerable spots, including hotels, parks and other places for checking traffic congestion. "These spots will be under a round-the-clock security cover. The parking alert system will inform all the commuters about parking availability in the areas concerned, to reduce the undue traffic load. More pelican signals will also be installed at crossings for safer movement of both pedestrians and vehicular traffic," he added.

A senior Delhi Police officer, who asked not to be named, said several issues such as road markings, signages and diver-

ROAD AHEAD

- All out-of-order traffic lights and signals will soon be repaired
- Traffic police are mapping spots vulnerable to congestion, including hotels and parks
- More pelican signals will be installed at crossings for safer movement of vehicles and pedestrians
- The parking alert system will inform commuters about parking availability

sions at 290 road junctions, which will be implemented ahead of the G20 summit, were discussed last week in a meeting with different agencies including DDA, MCD and CPWD.

"The road design between Pragati Maidan and Lodhi Road and traffic congestion in several areas such as Delhi Cantonment and Dhoola Kuan were also discussed in the multi-agency meeting. Taking a serious note of these traffic issues, the Delhi LG has categorically asked all the agencies to rectify the issues before July 1," said the officer who asked not to be named.

"To reduce the vehicular movement during the summit, we have sought help from Haryana and Uttar Pradesh from where thousands of vehicles come to Delhi every day. If needed, we may also seal the borders linking Delhi with other states. Dedicated traffic advisories in this connection will be issued later," he said.

The officer added that designated gates, lounges and help desks will be installed at Indra Gandhi International Airport during the summit.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

अमर उजाला

नई दिल्ली | बुधवार, 8 फरवरी 2023

अमर उजाला

एकांत कारावास के खिलाफ याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

जवाब दाखिल करने के लिए दिया है छह सप्ताह का समय

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एकांत कारावास से जुड़े प्रावधानों की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई 23 मई को होगी। अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल ने अपनी जनहित याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 (दोनों एकांत कारावास से संबंधित हैं) के साथ-साथ जेल अधिनियम, 1894 की कई धाराओं को चुनौती दी है। सिंघल ने तर्क दिया है कि एकांत कारावास को न तो आईपीसी और न ही जेल अधिनियम में परिभाषित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह एक अतिरिक्त सजा है और एक मनमानी न्यायिक और पुलिस शक्ति है जिसका सजा

याची ने कहा, यह बर्बर, दुखदाई और अमानवीय प्रथा

से कोई संबंध नहीं है। यह कानून का घोर विचलन है और कोई भी अदालत यह नहीं मान सकती है कि सिर्फ इसलिए कि एक जघन्य अपराध किया गया है एक अपराधी भी एकांत कारावास का हकदार है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एकांत कारावास एक वास्तविक बिच्छू का विषैला घातक डंक है, यह दुखदायी, बर्बर और एक अमानवीय प्रथा है जो कैदियों को जेल अधिकारियों से गाली-गलौज करने, जबरदस्ती और हठधर्मी से मनमानी करने, झगड़ा करने, यहां तक कि जेल अधिकारियों को जवाब देने के परिणाम के रूप में जेल के छोटे-मोटे उल्लंघनों पर घिनौनी, बदबूदार कालकोठरी में कैदियों को डालकर दी जाती है। याची ने कहा, एकांत कारावास अमानवीय है क्योंकि यह संवेदी, दृश्य और सामाजिक समाज से एक कैदी को काट देता है।

बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी मौलवी की छह साल की जेल की सजा बरकरार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी मौलवी को दी गई छह साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा एक 'मौलवी' में बहुत विश्वास और भरोसा होता है जो दूसरों को पवित्र कुरान के सिद्धांतों को सिखाता है और श्रद्धा से देखा है ऐसे में दोषी को राहत देने का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने दोषी की अपील खारिज करते हुए उसकी सजा को रद्द या कम करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा वह किसी भी अनुग्रह के लायक नहीं है क्योंकि दोषी के पास बहुत विश्वास की स्थिति थी जिसे उसने एक भोली बच्ची का यौन उत्पीड़न करके तोड़ा। ब्यूरो

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों का आज से निशुल्क इलाज करने का निर्देश

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को निशुल्क इलाज प्रदान का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो अस्पताल प्रशासन से पिछले 20 वर्ष के इलाज के रूप में पैसे की रिकवरी का आदेश जारी किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि अस्पताल प्रशासन ने डीडीए से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 25 प्रतिशत मरीजों को निशुल्क इलाज देने के नाम पर सस्ती दवाएं पर भूमि ली थी, लेकिन जमीन लेने के समय से शर्त का पालन नहीं किया। पीठ ने कहा, यह सरासर गरीब मरीजों से धोखा है और डीडीए द्वारा तय शर्तों का भी उल्लंघन है। पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल प्रशासन के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन यदि बुधवार से तय शर्त के अनुसार गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज प्रदान करना शुरू करता है तो पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ब्यूरो

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर 33 ढांचे ढहाए

नई दिल्ली। सड़कों व फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को निगम ने 12 जोन में बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 33 स्थायी व अस्थायी ढांचे ढहाकर सामान जव्त किया गया। इस अभियान में डीडीए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस की टीम ने भी सहयोग किया। दिल्ली सरकार ने सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी निगम को सौंपी है।

जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर निगम सभी सड़कों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अन्य एजेंसियों के साथ-साथ सफाई और रखरखाव के लिए अभियान चला रहा है। विशेष अभियान के तहत मध्यक्षेत्र में गोविंदपुरी, ओखला, सरिता विहार, अंसारी रोड, दयानंद रोड, महावीर वाटिका, परदा बाग और दरियागंज में अभियान चलाया गया। जनरल ब्रांच की टीम ने दो किमी के दायरे से अतिक्रमण हटाया और 22 सामान जव्त किया। रोहिणी जोन ने तीन वाडों में चार किमी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया। रोहिणी जोन ने पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन और नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास अभियान चलाया और छह सामान जव्त किया। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS—

पंजाब केसरी
DELHI

DATED—

मरवरी, 2023 ▶ बुधवार 18

समीक्षा बैठक

हर घर सीवर कनेक्शन से यमुना को साफ करने में भी मिलेगी मदद: मुख्यमंत्री

युद्ध स्तर पर करें हर घर को सीवर से कनेक्ट: केजरीवाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को हर घर को सीवर कनेक्शन और यमुना सफाई परियोजना को समीक्षा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए कि दिल्ली में एक घर भी सीवर कनेक्शन से वंचित न हो। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि ईस्ट दिल्ली में मार्च तक और नार्थ ईस्ट दिल्ली में जून 2023 तक 100 फीसदी घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। हर घर सीवर कनेक्शन से यमुना को साफ करने में भी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली को सीवर नेटवर्क से जोड़ना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि यमुना में जरा भी गंदा पानी न गिरने पाए। उन्होंने कहा कि हर घर को सीवर कनेक्शन और यमुना सफाई परियोजना को अब हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोरभ भारद्वाज, मुख्य सचिव समेत दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत अभी तक सीवर नेटवर्क से जुड़ चुके घरों की जानकारी ली। उसके बाद शेष बचे घरों का स्टेटस जाना।

सीएम ने यमुना सफाई योजना का लिया जायजा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना सफाई परियोजना के संदर्भ में सीवर जंक्चर की स्थिति की भी समीक्षा की। दिल्ली में सीवेज का 100 फीसद उपचार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने को लेकर 4 फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें ओखला, दिल्ली गेट और सोनिया विहार में 3 नए एसटीपी का निर्माण, 40 नए डीएसटीपी का निर्माण, 3 मौजूदा एसटीपी का पुनर्वास और 18 मौजूदा एसटीपी की उन्नयन और क्षमता बढ़ाना शामिल है।



अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते केजरीवाल।

तीन नए एसटीपी के निर्माण में प्रगति...

दिल्ली में बन रहे तीन नए एसटीपी में से 30 एमजीडी क्षमता का ओखला एसटीपी जून 2023 तक और 7 एमजीडी क्षमता के सोनिया विहार एसटीपी सितंबर 2023 तक पूरे हो जाएंगे, जबकि 10 एमजीडी क्षमता के दिल्ली गेट एमजीडी के लिए संबंधित विभाग जमीन के लिए डीडीए द्वारा आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के 40 नए डीएसटीपी सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर में 92 एमजीडी की क्षमता जोड़ेंगे। इनमें से 29 डीएसटीपी दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएंगे। वहीं मौजूदा तीन एसटीपी के रिहैबिलिटेशन के माध्यम से दिल्ली सरकार अपने नेटवर्क में 70 एमजीडी की क्षमता जोड़ेंगी। कौडली का 25 एमजीडी क्षमता का फेज-2 जून 2023 तक तैयार हो जाएगा। 40 एमजीडी क्षमता का रिटाला एसटीपी भी जून 2023 तक तैयार हो जाएगा, जबकि फेज दो के यमुना विहार के 5 एमजीडी क्षमता का एसटीपी सितंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा। वहीं मौजूदा 18 एसटीपी का अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

जून 2023 तक सीवर नेटवर्क से जुड़ेंगे नार्थ ईस्ट दिल्ली में 100 फीसदी घर

सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों से पूछा कि पूर्वी दिल्ली में अभी तक जिन घरों तक सीवर कनेक्शन नहीं पहुंचा है, उन घरों को कब तक सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा? डीजेबी के अधिकारियों ने बताया कि इन घरों को मार्च 2023 तक सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। जून 2023 तक नार्थ ईस्ट दिल्ली में 100 फीसद घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। डीजेबी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि कुछ जगहों पर एसटीपी सीवेज को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। उस पर काम चल रहा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।